बलवन्त राय मेहता समिति (Balwant Rai Mehta Committee)

भारत में पंचायतों को ग्रामीण विकास का प्रभावशाली माध्यम बनाने और पंचायतों की सीमित सफलता का मूल्यांकन करके उपयोगी सुझाव देने के लिए सरकार ने सन् 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की जिसे 'बलवन्त राय मेहता समिति' कहा जाता है। बलवन्त राय मेहता उस समय सांसद थे (संसद के सदस्य)। इस समिति ने लगभग 6 महीनों तक देश के विभिन्न हिस्सों में ग्राम पंचायतों का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने यह माना कि स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण योजनाओं में जनता की सहभागिता बहुत कम है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए यह जरूरी है कि एक ऐसी पंचायत राज व्यवस्था स्थापित की जाय जिसमें ग्रामीणों का अधिक से अधिक सहभाग हो। यह काम केवल ग्राम पंचायतों के द्वारा ही सम्भव नहीं है।

समिति ने सुझाव दिया कि लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए ग्राम पंचायत की जगह एक तीन स्तरों वाली व्यवस्था (Three-tier System) स्थापित की जाए। इसका तात्पर्य है कि गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद स्थापित करके उन्हें एक-दूसरे

Created By Sign Doc

से इस तरह जोड़ा जाय जिससे गाँवों का स्थानीय शासन अधिक व्यवस्थित बन सके। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि इन तीनों स्तरों की पंचायतों को अधिक आर्थिक साधन और अधिकार दिये जायें। बलवन्त राय मेहता समिति ने इसी योजना को 'पंचायती राज व्यवस्था' के नाम से सम्बोधित किया। जनवरी, 1958 में सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद केन्द्र सरकार ने एक कानून बनाकर सन 1959 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारम्भ किया गया और यह आशा की गयी कि अब ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में ग्रामीण जनता पहल करेगी, उत्साह एवं उत्तरदायित्व का परिचय देगी और आवश्यक मात्रा में जनसहयोग प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक सत्ता को निचले स्तरों तक अर्थात ग्रामीण स्तरों तक हस्तान्तरित किया गया। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत स्वयं जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को स्थानीय प्रशासनिक अधिकार सौंपने की व्यवस्था की गयी ताकि वे ये अनुभव करें कि योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में उनका प्रभावशाली योग है। इस प्रकार पंचायती राज योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न ग्रामों में पंचायतों की स्थापना की गयी।

Created By Sign Doc